

## राजनीतिक अपराधीकरण

### प्रलिस के लयः

एमकिस कयूरी, जनप्रतनिधित्व कानून, राजनीतिक अपराधीकरण ।

### मेन्स के लयः

राजनीतिक अपराधीकरण का कारण, प्रभाव और समाधान ।

## चर्चा में क्यों?

न्याय मत्तर (Amicus Curiae) द्वारा संकलित आँकड़ों के अनुसार, 1 दसंबर, 2021 तक देश भर की वभिन्न अदालतों में वधायकों से जुड़े कुल 4,984 आपराधिक मामले लंबित थे ।

- न्याय मत्तर (Amicus Curiae) को सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और वधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरति सुनवाई हेतु विशेष अदालतें स्थापति करने में मदद के लयि नयुक्त कयि था ।
- यह प्रवृत्ति राजनीतिक अपराधीकरण की बढ़ती घटनाओं को उजागर करती है ।
- न्याय मत्तर (शाब्दिक रूप से "अदालत का मत्तर") वह व्यक्त होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है तथा जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, विशेषज्ञता या अंतरदृष्टि प्रदान करके अदालत की सहायता करता है ।

## राजनीतिक अपराधीकरण:

- इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है, जसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य वधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं ।
- यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साँटगाँट के कारण होता है ।

## आपराधिक छवके उम्मीदवारों की अयोग्यता का कानूनी पहलू:

- भारतीय संवधान में संसद या वधिनसभाओं के लयि चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्त की अयोग्यता के वषिय में उपबंध नहीं कयि गया है ।
- लोक प्रतनिधित्व अधनियम, 1951 में वधायिका का चुनाव लड़ने के लयि किसी व्यक्त को अयोग्य घोषति करने के मानदंडों का उल्लेख है ।
  - इस अधनियम की धारा 8 ऐसे दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है जनि पर केवल मुकदमा चल रहा है और दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है । इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कउन पर लगा आरोप कतिना गंभीर है ।
  - इस अधनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतरगत प्रावधान है कयिद कोई वधायिका सदस्य (सांसद अथवा वधायक) हत्या, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जैसे अपराधों में लपित है, तो उसे इस धारा के अंतरगत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लयि अयोग्य घोषति कर दयि जाएगा ।

## अपराधीकरण का कारण:

- कार्यान्वयन का अभाव: राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लयि बने कानूनों और नरिणयों के कार्यान्वयन की कमी के कारण इसमें बहुत मदद नहीं मली है ।
- संकीर्ण स्वार्थ: राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हसिसा जातयि धर्म जैसे सामुदायिक हतियों से प्रभावति होकर मतदान करता है ।
- बाहुबल और धन का उपयोग: गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलयि वे दल के चुनावी अभयान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है ।

- इसके अतिरिक्त कभी-कभी तो मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रतियोगी उम्मीदवार अपराधिक प्रवृत्त के होते हैं।

## SC LEADS FIGHT TO CLEAN UP POLLS

### CASES THAT LED TO THE RULINGS

**2002** SC directs all candidates to file affidavit detailing their criminal antecedents, educational qualification and details of their assets. Upholds voters' right to know about a candidate's antecedents to make an informed choice (Association of Democratic Reforms)



(People's Union for Civil Liberties)

**Mar | 2014** SC orders trial courts to hold **day-to-day trial in criminal cases** pending against sitting MPs and MLAs and complete it within one year from framing of charges

**Aug** SC recommends to **PM/CMs not to include persons**, against whom charges have been framed in serious offences, in their council of ministers (Manoj Narula)

**July | 2013** SC quashes provision in Representation of the People Act that allowed MPs and MLAs to continue their membership in a House by merely filing appeal against their conviction and sentence of more than two years in a higher court. This meant **MPs and MLAs would be disqualified immediately on conviction and sentence of more than 2 years**. (Lily Thomas and Lok Prahari case)

**Sept** SC asks EC to provide **'none of the above' choice to voters** to exercise their right to express no confidence against all candidates in fray

**Mar | 2016** SC refers to 5-judge Constitution bench whether **framing of charge in heinous crimes** (which entails imprisonment of five years or more) against an MP or MLA would disqualify him. This also meant—whether a person against whom charges framed in serious offences be debarred from contesting elections (Public Interest Foundation)



//

### प्रभाव:

- **स्वतंत्र और नष्पिकष चुनाव के सिद्धांत के वरिद्ध:**
  - यह एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करने के लिये मतदाताओं की पसंद को सीमिति करता है।
  - यह स्वतंत्र और नष्पिकष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जो कलोकतंत्र का आधार है।
- **सुशासन पर प्रभाव:**
  - प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन स्थापति करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावति होती है।
  - भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में यह प्रवृत्त यहाँ के संस्थानों की प्रकृत तथा वधायिका के चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छविको दर्शाती है।
- **लोक सेवकों के कार्य पर प्रभाव:**
  - इससे चुनावों के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा लोक सेवकों के काम पर असर पड़ता है।
- **सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा:**
  - यह समाज में हिसा की संस्कृतिको प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिये एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

### आगे की राह

- चुनाव सुधार पर बनी विभिन्न समितियों (दनिश गोस्वामी, इंदरजीत समिति) ने राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किये जाने की सफारिश की, जिससे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मल्लिगी और परिणामस्वरूप राजनीतिक अपराधीकरण को सीमिति कयि जा सकेगा।
- एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को वनियिमिति करना आवश्यक है, जिसके लिये नरिवाचन आयोग (Election

Commission) को मज़बूत करना ज़रूरी है।

- मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- भारत के राजनीतिक दलों की राजनीतिक अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के प्रति अनिच्छा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले पर विचार करना चाहिये।

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/criminalization-of-politics-2>

